बुधवार
15 जुलाई 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 172
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

राहुल गांधी को लेकर सत्ता पक्ष 'असहज'!

◆कार्यक्रम की अनुमति विवाद ने खोला नया सियासी मोर्चा
◆कांग्रेस का दावा-युवाओं में बढ़ती पकड़ से घबराई भाजपा
◆भाजपा ने कांग्रेस पार्टी के सभी आरोपों को बताया हताशा

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, लेकिन सियासी तापमान अभी से चढ़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर उठा विवाद अब केवल प्रशासनिक मसला नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे राजनीतिक संदेशों की लड़ाई में बदल गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता, युवाओं से उनके संवाद और बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दों पर उनकी आक्रामकता से असहज है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर पैदा हुए विवाद ने उत्तराखंड की राजनीति में नया मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि राहुल गांधी का कार्यक्रम केवल एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि था, तो फिर उसे लेकर इतनी असहजता क्यों दिखाई गई? पार्टी का दावा है कि सत्ता पक्ष को जनता के बीच राजनीतिक मुकाबला करना चाहिए, न कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सहारे विपक्ष की आवाज को कमजोर करने की कोशिश करनी चाहिए।

कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी आज युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक भाजपा को सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है कि राहुल गांधी इन सवालों को सीधे जनता के बीच ले जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर दबाव और विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश बता रही है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी राजनीतिक छवि में बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें कांग्रेस केवल राष्ट्रीय नेता के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज के तौर पर पेश कर रही है। उत्तराखंड जैसे राज्य में, जहां बेरोजगारी, पलायन, भर्ती घोटाले और शिक्षा से जुड़े सवाल लगातार उठते रहे हैं, राहुल गांधी का कार्यक्रम भाजपा के लिए एक नई चुनौती माना जा रहा है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा को डर है कि राहुल गांधी यदि छात्रों और युवाओं के बीच सीधे संवाद स्थापित करने में सफल रहे, तो चुनाव से पहले राजनीतिक नैरेटिव बदल सकता है। पार्टी का दावा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में आएं, क्योंकि इससे सरकार के विकास दावों पर सवाल खड़े होंगे। दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा जैसी मजबूत संगठनात्मक पार्टी किसी एक नेता से भयभीत नहीं हो सकती। उनका तर्क है कि प्रशासनिक निर्णय कानून-व्यवस्था और व्यवस्था की जरूरतों के आधार पर लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस हर बार उन्हें राजनीतिक रंग देकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है।

फिर भी यह सच है कि उत्तराखंड में राहुल गांधी की मौजूदगी और उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को भाजपा हल्के में नहीं ले रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी घोषणा से पहले यदि कांग्रेस ने राहुल गांधी को युवाओं और छात्रों के बीच लगातार सक्रिय रखा, तो इससे विपक्ष को एक नया राजनीतिक नैरेटिव मिल सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे विवाद को भाजपा की बेचैनी और डर की राजनीति के रूप में पेश कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की औपचारिक घोषणा से पहले यह टकराव और तेज होने के संकेत हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को राज्य में परिवर्तन, सवाल और जनसरोकारों की आवाज के रूप में स्थापित करना चाहती है, जबकि भाजपा अपने संगठन, सरकार और विकास कार्यों के सहारे जवाब देने की तैयारी में है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा भाजपा के लिए सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम है, या फिर चुनाव से पहले उभरता हुआ ऐसा सियासी खतरा, जिससे सत्ता पक्ष अभी से असहज दिख रहा है?

दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती पॉक्सो एक्ट में हुई गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

नैनीताल। भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। जिस युवती ने सबसे पहले नरेश पांडे के खिलाफ दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था अब वही युवती खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है। एक अन्य युवती की शिकायत के आधार पर मल्लीताल पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मानव तस्करी, जबरन दुष्कर्म कराने का प्रयास तथा मारपीट व जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल

भेज दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले में नया मोड़ तब आया, जब एक अन्य युवती ने कोतवाली मल्लीताल में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पहली शिकायतकर्ता युवती उसे बहला फुसलाकर काठगोदाम स्थित एक होटल में ले गई थी। वहां पहले से मौजूद नरेश पांडे के सामने उसे जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गईं।

शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि घटना के समय उसकी उम्र 17 वर्ष 11 माह थी जिसके चलते मामला पाक्सो एक्ट के दायरे में भी आया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए मल्लीताल पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता युवती के खिलाफ पाक्सो एक्ट, मानव तस्करी तथा अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मंगलवार सुबह पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

दून वैली मेल

संपादकीय

लोकतंत्र की ताकत

उत्तराखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे मतदाता सूची को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाने का अभियान बता रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इसके बहाने कुछ वर्गों के मतदाताओं को सूची से बाहर करने की आशंका पैदा की जा रही है। अब जब 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की बात सामने आई है, तो यह चिंता और बढ़ गई है कि कहीं तकनीकी त्रुटियों के नाम पर पात्र नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। यदि नोटिस का प्रारूप स्पष्ट नहीं हुआ, जवाब देने की प्रक्रिया सरल नहीं रखी गई और दस्तावेजों की सूची अत्यधिक जटिल हुई, तो इसका सीधा असर मताधिकार पर पड़ सकता है। उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में मतदाता सूची का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहां लगातार पलायन, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में आवाजाही, सैनिक परिवारों की विशेष परिस्थितियां और तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र मतदाता सूची को जटिल बनाते हैं। ऐसे में पुनरीक्षण आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी सरल और पारदर्शी होनी चाहिए कि किसी पात्र नागरिक का नाम केवल तकनीकी कारणों से न कटे। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को पहचान, निवास, आयु और पात्रता से जुड़े वैध दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर लोकतंत्र टिका है। इसलिए आयोग की हर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिस पर किसी भी दल या मतदाता को संदेह न हो। यदि किसी नागरिक का नाम हटाया जाता है तो उसके पीछे स्पष्ट कारण हो, समय पर सूचना मिले और उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर भी मिले। लोकतंत्र में मताधिकार केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति है। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस देने जैसी बड़ी कार्रवाई तभी विश्वसनीय मानी जाएगी, जब उसमें पारदर्शिता, समयबद्धता और मानवीय संवेदनशीलता तीनों मौजूद हों। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। यदि किसी प्रक्रिया में वास्तविक खामी है तो उसे तथ्यों और प्रमाणों के साथ सामने लाया जाए। लेकिन यदि बिना पर्याप्त आधार के हर प्रशासनिक कदम को राजनीतिक साजिश बताया जाएगा, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर होगा। दूसरी ओर, सरकार और प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरी प्रक्रिया किसी भी प्रकार के पक्षपात के आरोप से परे दिखाई दे। नोटिस, जवाब और दस्तावेजों की पूरी व्यवस्था इतनी स्पष्ट हो कि आम मतदाता को यह न लगे कि उसके अधिकार पर अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसे समय में मतदाता सूची का हर संशोधन राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग, प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों को अतिरिक्त संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर होना लोकतंत्र की हार होगी, वहीं किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में बने रहना चुनावी शुचिता पर प्रश्नचिह्न लगाएगा। 19 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया यदि सही ढंग से नहीं संभाली गई, तो यह शुद्धिकरण अभियान भरोसे के संकट में बदल सकता है। लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूची की शु(ता से ही नहीं, बल्कि उस शु(ता पर जनता के विश्वास से भी तय होती है। एसआईआर की सफलता इसी कसौटी पर परखी जाएगी कि हर पात्र मतदाता निश्चिंत होकर कह सके मेरा वोट सुरक्षित है, मेरा अधिकार सुरक्षित है।

छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन

संवाददाता

देहरादून। छात्रों की गूँज कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

आज यहां छात्रों की गूँज कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह, उपनेता सदन भुवन कापड़ी, पूर्व विधायक राजपुर रोड राजकुमार, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परीक्षाओं की निष्पक्षता व युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। कार्यक्रम में यह भी जानकारी दी गई कि 17 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद करेंगे, जिसमें युवाओं के मुद्दों, शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन महेंद्र राणा (पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस), प्रवीन रावत प्रिंस (जिला पंचायत सदस्य, देहरादून) एवं शूरवीर सिंह चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस (पूर्व महासचिव, डीएवी कॉलेज, देहरादून) द्वारा किया गया।

भाजपा के भीतर 'बगावत के सुर'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच सत्तारूढ़ भाजपा के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रुद्रप्रयाग जिले में भाजपा के कई पदाधिकारियों के एक साथ इस्तीफा देने से पार्टी के भीतर सुलग रहा असंतोष अब सार्वजनिक मंच पर आ गया है। इस्तीफा देने वाले नेताओं का सबसे बड़ा आरोप है कि क्या हम सिर्फ झंडे-डंडे उठाने के लिए हैं? भाजपा हमेशा अपने अनुशासित संगठन और समर्पित कार्यकर्ताओं पर गर्व करती रही है। पार्टी का दावा रहा है कि उसका सबसे बड़ा आधार कार्यकर्ता है, न कि केवल बड़े चेहरे। लेकिन रुद्रप्रयाग की घटना ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी ही स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, बल्कि संगठनात्मक संवाद में कमी का संकेत भी हो सकता है।

इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि वर्षों तक पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को अब केवल कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने, झंडे उठाने और नारे लगाने तक सीमित कर दिया गया है। निर्णय लेने का अधिकार कुछ चुनिंदा नेताओं तक सिमट गया है। उनका कहना है कि संगठन में अब मेहनत से ज्यादा नजदीकी का महत्व बढ़ गया है। यदि यह धारणा कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत होती है, तो यह किसी भी राजनीतिक दल के लिए गंभीर चेतावनी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा का संगठन तेजी से सत्ता-केंद्रित हुआ है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय की बात तो होती है, लेकिन कई जिलों में पुराने कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि उनकी भूमिका धीरे-धीरे कम होती जा रही है। चुनाव के समय उनकी याद आती है, लेकिन निर्णयों और नियुक्तियों के समय उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। रुद्रप्रयाग की घटना ने इसी बहस को फिर हवा दे दी है।

◆सामूहिक इस्तीफों ने खोली संगठन की अंदरुनी दरारें
◆चुनावी रण से पहले भाजपा के लिए खतरे की घंटी
◆क्या भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ झंडे-डंडे उठाने के लिए

सबसे अहम सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल रुद्रप्रयाग तक सीमित रहेगा? या फिर यह असंतोष दूसरे जिलों में भी दिखाई देगा? उत्तराखंड की राजनीति में अक्सर स्थानीय स्तर की नाराजगी समय रहते संभाल ली जाती रही है, लेकिन यदि कार्यकर्ताओं को यह संदेश गया कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो चुनावी वर्ष में इसका असर बूथ स्तर तक दिखाई दे सकता है। भाजपा की चुनावी ताकत हमेशा उसका मजबूत बूथ नेटवर्क रहा है। यही कार्यकर्ता घर-घर जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, मतदाताओं तक पहुंचते हैं और चुनावी मशीनरी को गति देते हैं। यदि यही कार्यकर्ता निराश हो जाएं तो किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। चुनाव पोस्टरों और सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि बूथ पर खड़े कार्यकर्ताओं के भरोसे जीते जाते हैं।

उत्तराखंड में भाजपा के सामने विपक्ष से पहले अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस लगातार भाजपा पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाती रही है। अब यदि भाजपा के अपने पदाधिकारी भी संगठनात्मक उपेक्षा की बात करने लगें, तो विपक्ष को बैठे-बिठाए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व की ओर से अब तक इस मामले को लेकर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के सामने दो विकल्प हैंकृया तो वह इसे कुछ नाराज नेताओं का व्यक्तिगत मामला मानकर आगे बढ़ जाए, या फिर इसे संगठन के लिए चेतावनी मानते हुए संवाद की प्रक्रिया शुरू करे। राजनीतिक अनुभव बताता है कि चुनाव से पहले छोटे दिखने वाले असंतोष कई बार बड़े संकट का रूप ले लेते हैं।

उत्तराखंड की राजनीति में कार्यकर्ता हमेशा किसी भी दल की रीढ़ रहे हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों ने कठिन दौर में कार्यकर्ताओं के दम पर ही अपनी राजनीतिक जमीन बचाई है। ऐसे में यदि किसी दल के कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से यह कहने लगें कि उन्हें केवल झंडे-डंडे उठाने तक सीमित कर दिया गया है, तो यह केवल संगठन का नहीं, नेतृत्व शैली का भी सवाल बन जाता है। रुद्रप्रयाग की घटना का राजनीतिक संदेश दूर तक जाएगा। विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन चुनावी माहौल बनने लगा है। ऐसे समय में सामूहिक इस्तीफे यह संकेत

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

3000 पेड़ों के लिए 'जेन जी' सड़क पर उतरी

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति और समाज में इन दिनों एक नया आंदोलन आकार ले रहा है। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी का है जिसे अक्सर मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित मान लिया जाता है। करीब 3000 पेड़ों की प्रस्तावित कटाई के विरोध में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां, चेहरे पर आक्रोश और आवाज में भविष्य की चिंता लिए इन युवाओं ने साफ संदेश दिया कि विकास जरूरी है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। छात्र, शोधार्थी, पर्यावरण कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि हजारों पेड़ों की बलि देकर विकास होगा तो आने वाली पीढ़ियों को केवल चौड़ी सड़कें मिलेंगी, लेकिन सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा और पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचेगा।

युवाओं का कहना है कि यह आंदोलन केवल 3000 पेड़ों को बचाने का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को बचाने का है। उनका तर्क है कि हिमालयी राज्य में एक-एक पेड़ का महत्व मैदानी इलाकों से कहीं अधिक है। यहां पेड़ केवल आक्सीजन नहीं देते, बल्कि जलस्रोतों को जीवित रखते हैं, भूस्खलन रोकते हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। युवाओं ने सवाल उठाया कि क्या किसी परियोजना का ऐसा विकल्प नहीं खोजा जा सकता जिसमें कम से कम पेड़ों की कटाई हो? क्या विकास का मतलब हर बार जंगलों को खत्म करना ही होगा?

इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई और देखते-देखते यह जन आंदोलन में बदलने लगी। इंस्टाग्राम, एक्स

❑उत्तराखंड में पर्यावरण बनाम विकास की नई जंग
❑युवाओं ने कहा-जंगल बचेंगे, तभी भविष्य बचेगा
❑सोशल मीडिया से सड़क तक पहुंच गया आंदोलन

और फेसबुक पर हजारों युवाओं ने पेड़ों को बचाने की अपील की। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। यह तस्वीर उत्तराखंड की बदलती युवा सोच को भी दर्शाती है। आज का युवा केवल नौकरी और करियर की बात नहीं कर रहा, बल्कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को भी अपनी प्राथमिकता बना रहा है। सरकार और संबंधित एजेंसियों का कहना है कि प्रस्तावित परियोजना राज्य के विकास और यातायात व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उनका दावा है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाएगा तथा कटने वाले पेड़ों के बदले प्रतिपूरक पौधरोपण भी किया जाएगा।

हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि 50-100 वर्ष पुराने पेड़ों की भरपाई केवल पौधे लगाकर नहीं की जा सकती। एक विकसित जंगल बनने में दशकों लगते हैं। जोशीमठ धंसाव, लगातार बढ़ते भूस्खलन, अनियमित बारिश, बादल फटना और सूखते धारे-नौले पहले ही हिमालय की संवेदनशीलता की चेतावनी दे चुके हैं। विशेषज्ञ लगातार कहते रहे हैं कि अनियोजित विकास और अंधाधुंध वृक्ष कटान भविष्य में और बड़े संकट पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से युवा पूछ रहे हैं कि यदि हर विकास परियोजना की पहली शर्त पेड़ों की कटाई होगी, तो उत्तराखंड की हरियाली आखिर बचेगी कैसे?

विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है और सरकार से परियोजना की समीक्षा की मांग की है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की बन गई है, जिन्होंने राजनीतिक दलों से इतर पर्यावरण को केंद्र में रखकर अपनी बात रखी है। सवाल जो सरकार के सामने हैं क्या परियोजना का वैकल्पिक डिजाइन संभव है? क्या 3000 पेड़ों की कटाई अंतिम विकल्प है? क्या स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन सार्वजनिक किया

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

वर्ग चार भूमि नियमितीकरण का लाभ चकराता परगने के तीनों तहसीलों को देने की मांग

विकासनगर(आरएनएस)। जौनसार बावर परगने में वर्ग-चार भूमि नियमतीकरण को लेकर उत्पन्न भ्रम की स्थिति के बीच जल, जंगल, जमीन संरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चकराता परगने की सभी तहसीलों को योजना का लाभ देने की मांग उठाई।

समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और उपाध्यक्ष श्याम दत्त जोशी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व के अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव तथा संयुक्त सचिव अर्पण कुमार राजू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 25 अप्रैल 2026 की बैठक के कार्यवृत्त में केवल त्यूनी तहसील का उल्लेख होने से कालसी और चकराता तहसीलों के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

उन्होंने मांग की कि चकराता परगने की तीनों तहसीलों त्यूनी, कालसी और चकराता को वर्ग-4 भूमि नियमतीकरण का लाभ दिया जाए।समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने बताया कि अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने पत्र का अवलोकन करने के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शासनादेश में पूरे चकराता परगने की तीनों तहसीलों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी शासनादेश भी तीनों तहसीलों पर लागू था और बैठक के कार्यवृत्त में केवल त्यूनी तहसील का उल्लेख होने से भ्रम की स्थिति बनी है। इसे स्पष्ट करते हुए संशोधित आदेश जारी किए जाएंगे।शासन के इस आश्वासन पर प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में दिग्विजय सिंह, श्याम दत्त जोशी, प्रवीण तोमर, गीता राम जोशी, मनोज खन्ना, नैन सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

एक साल से खतरे की जद में मंजकोट इंटर कॉलेज का भवन

नई टिहरी(आरएनएस)। राजकीय इंटर कॉलेज मंजकोट में अतिवृष्टि के दौरान पिछले साल गिरी पीएमजीएसवाई सड़क की सुरक्षा दीवार का मलबा नहीं हट पाया। विद्यालय भवन के ऊपर सुरक्षा दीवार का शेष हिस्सा लटका होने से भवन को खतरा बना हुआ है। इस मामले में धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने डीएम को पत्र भेजकर एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है।

उन्होंने डीएम को संबंधित विभाग को तत्काल मलबा हटाने और सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश देने को कहा है।पत्र में विधायक ने कहा है कि विकासखंड थौलधार के राजकीय इंटर कॉलेज मंजकोट में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत मैंडखाल-गैर मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार 14 अगस्त 2025 को आंशिक रूप से विद्यालय भवन पर गिर गई थी।

इस घटना में विद्यालय के दो कक्षा-कक्ष, कार्यालय कक्ष और वर्चुअल लैब क्षतिग्रस्त हो गए थे। विद्यालय प्रशासन ने इसकी सूचना जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को दी थी लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो मलबा हटाया गया और न ही सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण किया गया।

विद्यालय में कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई इन्हीं प्रभावित कक्षों के आसपास संचालित हो रही है। विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वैकल्पिक व्यवस्था करना भी संभव नहीं हो पा रहा है। विधायक पंवार ने डीएम से छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मलबा हटाने, सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण कराने को कहा है।

बोंगा-भैलूड़ा मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य लटका

उत्तरकाशी(आरएनएस)। जिला मुख्यालय के समीप बोंगा-भैलूड़ा मोटरमार्ग पर आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। कार्यदायी संस्था पीएमजीएसवाई की ओर से सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया था लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क का काम लंबे समय से बंद पड़ा है। इससे सड़क की स्थिति और खराब हो गई है।

लदाड़ी से बोंगा-भैलूड़ा तक करीब पांच किमी लंबे मोटर मार्ग के चौड़ीकरण और डामरीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग चार करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था ने सड़क निर्माण का काम शुरू तो किया लेकिन लंबे समय से कार्य बंद पड़ा है।अधूरे निर्माण के कारण मार्ग पर आवाजाही करना मुश्किल हो गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर फैली निर्माण सामग्री, गड्ढे और खराब सतह के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण रविंद्र सिंह राणा, जयेंद्र सिंह महर, गोविंद सिंह नेगी और पारेश्वर बिजल्वाण ने विभाग से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की है।वहीं, पीएमजीएसवाई के अधिकारियों का कहना है कि बरसात के कारण सड़क निर्माण कार्य फिलहाल रोकना पड़ा है। मौसम सामान्य होते ही काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता हरीश बिजल्वाण ने बताया कि मार्ग पर डामरीकरण का कार्य शेष है जिसे बरसात समाप्त होने के बाद प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा।

पलायन के थपेड़ों में जमींदोज हो गई 'छानी'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। पहाड़ के गांवों की पहचान केवल पत्थर के मकानों, सीढ़ीनुमा खेतों और देवदार के जंगलों से ही नहीं होती थी, बल्कि उनकी आत्मा बसती थी छानी में। आज नई पीढ़ी के लिए यह केवल एक पुराना शब्द रह गया है, लेकिन कभी यही छानी पहाड़ के किसान की दूसरी दुनिया हुआ करती थी। खेतों की रखवाली से लेकर पशुपालन, घास-लकड़ी के संग्रह, खेती-बाड़ी और पारिवारिक जीवन तककृछानी पहाड़ की आत्मनिर्भर जीवनशैली का सबसे मजबूत आधार थी। आज जब पलायन के कारण गांव खाली हो रहे हैं और खेती लगातार सिमट रही है, तब सबसे पहले वीरान हुई हैं पहाड़ की छानियां। कभी जिनमें चूल्हा जलता था, पशुओं की घंटियां बजती थीं और बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा पसरा है।

बता दें कि छानी वह छोटा पत्थर और लकड़ी का पारंपरिक भवन होता था, जिसे गांव से कुछ दूरी पर खेतों या बुग्यालों के पास बनाया जाता था। इसका उद्देश्य केवल रहने की जगह उपलब्ध कराना नहीं था, बल्कि खेती और पशुपालन को सुविधाजनक बनाना था। बरसात और खेती के मौसम में परिवार के सदस्य कई-कई दिनों तक छानी में रहते थे। नीचे पशुओं के लिए गोठ और ऊपर रहने की व्यवस्था होती थी। मोटी पत्थर की दीवारें, स्लेट की छत और लकड़ी के मजबूत दरवाजे इसे मौसम के अनुकूल बनाते थे।

जब पहाड़ के गांवों में सड़कें नहीं थीं, मशीनें नहीं थीं और आधुनिक कृकृषि उपकरण उपलब्ध नहीं थे, तब छानी ही खेती का संचालन केंद्र होती थी। सुबह खेत, दिन में पशुपालन और शाम को चूल्हे की आगकृयही पहाड़ का जीवन था। दूध, दही, घी, मंडुवा, झंगोरा, राजमा और अन्य कृषि उत्पादों की पूरी व्यवस्था छानी के इर्द-गिर्द चलती थी। यही कारण था कि पहाड़ की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में छानी का विशेष महत्व था।

●पहाड़ की छानियों में बसते थे खेत, पशु व परिवार के सपने
●महानगरों की चकाचौंध ने उजाड़ दी पहाड़ की यह धरोहर
●अब सिर्फ खंडहर और यादों में सिमट कर रह गई है छानी

छानी केवल ईंट-पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि लोक संस्कृति का विद्यालय भी थी। रात के समय बुजुर्ग लोककथाएं सुनाते थे, महिलाएं लोकगीत गाती थीं और बच्चे खेती-पशुपालन के गुर सीखते थे। पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान यहीं हस्तांतरित होता था। घास काटने, पशुओं की देखभाल, मौसम पहचानने, बीज सुरक्षित रखने और जंगल के साथ संतुलन बनाकर जीने की सीख छानी के जीवन का हिस्सा थी। उत्तराखंड में बढ़ते पलायन ने गांवों के साथ-साथ छानियों को भी वीरान कर दिया। जब खेती छूटी, पशुपालन घटा और परिवार शहरों की ओर चले गए, तब छानियों के चूल्हे बुझ गए।

आज हजारों छानियां टूट चुकी हैं। कहीं छतें गिर गई हैं, कहीं दीवारों पर झाड़ियां उग आई हैं। कई स्थानों पर केवल पत्थरों के ढेर इस बात की गवाही देते हैं कि यहां कभी जीवन धड़कता था। यह नहीं कि सभी जगह ऐसा ही हो गया है। पहाड़ में कई स्थानों पर आज भी ग्रामीण परिवेश की यह झलक देखने को मिलती है पर नगण्य। आज के दौर में यदि इन पारंपरिक छानियों का संरक्षण किया जाए, तो इन्हें ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ सकेगी। यूरोप और हिमालय के कई क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि आवासों को विरासत पर्यटन से जोड़ा गया है। पहाड़ में भी ऐसी पहल छानियों को नया जीवन दे सकती है।

सीमेंट और कंक्रीट के आधुनिक मकानों के बीच छानी अब अतीत की निशानी बनती जा रही है। लेकिन यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि पहाड़ के श्रम, प्रकृति, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक जीवन का प्रतीक है। यदि आज इन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों और तस्वीरों में ही जान पाएंगी कि कभी उत्तराखंड का किसान खेतों के बीच बनी अपनी छानी में रहकर पूरे परिवार के साथ जीवन बिताता था।

आज के दौर में छानी को बचाना केवल पुरानी इमारतों को बचाना नहीं है, बल्कि पहाड़ की उस जीवन-प(ति को बचाना है जिसने सीमित संसाधनों में प्रकृति के साथ संतुलित और सम्मानजनक जीवन जीने की मिसाल पेश की। विकास की दौड़ में यदि हमारी छानियां खो गईं, तो हम केवल पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक स्मृति, लोकज्ञान और पहाड़ की आत्मा का एक अनमोल अध्याय भी खो देंगे।

देवभूमि में आस्था पर राजनीतिक 'महाभारत'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। बदरीनाथ धाम के चढ़ावे से जुड़े विवाद ने अब उत्तराखंड की राजनीति में नया मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने कांग्रेस पर धार्मिक आस्था को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस लगातार पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का यह दौर अब व्यक्तिगत कटाक्ष तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंदिरों में पूजा-अर्चना करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मणों के प्रति अनास्था का माहौल बनाना सनातन परंपरा और धार्मिक व्यवस्था में अविश्वास पैदा करने जैसा है। उनका कहना था कि कुछ व्यक्तियों की कथित गलती के आधार पर पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करना उचित नहीं है।

चमोली ने कांग्रेस पर सीधा राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि यदि गणेश गोदियाल स्वयं किसी आरोपी को संरक्षण देने के दोषी नहीं माने जा सकते, तो फिर बिना जांच पूरी हुए सरकार, मुख्यमंत्री और पूरी मंदिर समिति को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। भाजपा का कहना है कि किसी भी मामले में जिम्मेदारी तथ्यों और जांच के आधार पर तय होनी चाहिए न कि राजनीतिक आरोपों से। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भावनात्मक मुद्दा बनाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। पार्टी का दावा है कि सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बदरीनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यदि चढ़ावे से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है, तो सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को केवल जांच की घोषणा नहीं, बल्कि पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्य सार्वजनिक करने चाहिए।

बता दें कि बदरीनाथ चढ़ावा विवाद अब केवल एक प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं रह गया है। यह भाजपा और कांग्रेस के बीच आस्था, जवाबदेही और राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई का नया प्रतीक बनता जा रहा है। भाजपा इस मुद्दे को आस्था पर राजनीति के रूप में पेश कर रही है, जबकि कांग्रेस इसे आस्था की सुरक्षा और जवाबदेही का प्रश्न बता रही है। उत्तराखंड में जहां धार्मिक आस्था चुनावी विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, वहीं बदरीनाथ जैसे प्रतिष्ठित धाम से जुड़ा विवाद राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में दोनों दल इस मुद्दे को अपने-अपने पक्ष में जनमत बनाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। क्योंकि अंतत: राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि जांच के परिणाम ही तय करेंगे कि जनता किसके तर्क पर अधिक भरोसा करती है।

मिक्सर की जार को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके, होगा आसान

आजकल मिक्सर लगभग हर रसोई में देखने को मिलता है। इसका उपयोग कई चीजों को पीसने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसका उपयोग करने के बाद इसे साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर जार में कुछ चिपक जाए तो इसे साफ करने में काफी मेहनत लगती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर मिक्सर की जार को आसानी से साफ किया जा सकता है।

गर्म पानी और साबुन का करें इस्तेमाल- मिक्सर की जार को साफ करने के लिए गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार में गर्म पानी भरें, फिर इसमें थोड़ा साबुन डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक नरम स्पंज से जार को हल्के हाथों से साफ करें। इससे जार की अंदरूनी गंदगी और दाग हट जाएंगे और यह चमकदार बनेगा। ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो ताकि जार टूट न जाए।

सिरका और खाने का सोडा भी है असरदार- मिक्सर की जार को साफ करने के लिए सिरका और खाने का सोडा का मिश्रण भी अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार में एक चम्मच सिरका और एक चम्मच खाने का सोडा डालें, फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इससे जार में जमा गंदगी नरम हो जाएगी। इसके बाद नरम स्पंज से जार को रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। यह तरीका जार को नई जैसी चमकदार बनाएगा।

नींबू का रस भी करेगा मदद- नींबू का रस भी मिक्सर की जार को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार में आधा कप पानी भरें, फिर उसमें दो चम्मच नींबू का रस डालें और इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद सफाई के लिए साबुन डालकर मिक्सर को चलाएं, फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। इससे जार की अंदरूनी गंदगी साफ हो जाएगी और यह चमकदार बनेगा।

खाने का सोडा और पानी का मिश्रण बनाएं- खाने का सोडा और पानी का मिश्रण भी मिक्सर की जार को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार में एक चम्मच खाने का सोडा और एक चम्मच पानी डालें, फिर इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें ताकि खाने का सोडा अच्छी तरह से फैल सके। इसके बाद एक नरम स्पंज से जार को हल्के हाथों से रगड़ें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। अंत में ठंडे पानी से धोकर साफ करें।

सफेद सिरका और गर्म पानी का मिश्रण बनाएं- सफेद सिरका और गर्म पानी का मिश्रण भी मिक्सर की जार को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले जार में आधा कप गर्म पानी भरें, फिर उसमें दो चम्मच सफेद सिरका डालें और इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद नरम स्पंज से जार को रगड़ें ताकि सारी गंदगी निकल जाए। अंत में ठंडे पानी से धोकर साफ करें।

मानसून में वॉशिंग मशीन का ऐसे रखें ध्यान, कपड़ों में नहीं आएगी सीलन की बदबू

बरसात के मौसम में हवा में नमी काफी बढ़ जाती है, जिसका असर वॉशिंग मशीन पर भी पड़ता है। धुलाई के बाद मशीन के अंदर बची नमी जल्दी नहीं सूखती और लंबे समय तक बनी रहती है। इससे ड्रम, रबर सील और डिटर्जेंट ट्रे में फफूंदी, बैक्टीरिया और बदबू बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसका असर मशीन के साथ-साथ कपड़ों की सफाई और उनकी खुशबू पर साफ दिखाई देने लगता है।

धुलाई के बाद यह काम जरूर करें- विशेषज्ञों की सलाह है कि हर धुलाई के बाद वॉशिंग मशीन का दरवाजा और डिटर्जेंट ट्रे कुछ घंटों के लिए खुली छोड़ दें। इससे अंदर की नमी आसानी से बाहर निकल जाती है और हवा का प्रवाह बना रहता है। दरवाजा बंद करने से पहले रबर की सील को सूखे और साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। टॉप-लोड मशीन इस्तेमाल करने वाले लोग भी धुलाई के बाद कुछ समय तक ढक्कन खुला रखें।

समय-समय पर करें मशीन की सफाई- हर दो से तीन सप्ताह में बिना कपड़ों के गर्म पानी के साथ वॉशिंग मशीन क्लीनर चलाना फायदेमंद माना जाता है। इससे अंदर जमी गंदगी, फफूंदी और बैक्टीरिया साफ होने में मदद मिलती है। मशीन को हमेशा हवादार जगह पर रखें और ऐसी जगह लगाने से बचें, जहां सीधे बारिश या अधिक नमी का असर पड़ता हो। इससे वॉशिंग मशीन काफी लंबे समय तक बेहतर स्थिति में बनी रहती है।

इन छोटी सावधानियों से बचेंगे बड़े खर्च से- वॉशिंग मशीन के बिजली कनेक्शन, पावर सॉकेट और अर्थिंग की समय-समय पर जांच कराते रहें, ताकि नमी से होने वाली खराबी से बचा जा सके। अगर मशीन से बदबू आने लगे, पानी ठीक से बाहर न निकले या कोई दूसरी समस्या दिखे तो तुरंत जांच कराएं। समय पर सर्विस कराने से छोटी खराबी बड़ी नहीं बनती और मशीन की कार्यक्षमता तथा उम्र दोनों लंबे समय तक बेहतर बनी रहती हैं।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

लगातार देर तक काम करना हो सकता है सेहत के लिए नुकसानदायक

जीवनयापन करने के लिए काम करना बहुत जरूरी होता है, हाल ही में इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी, जिसके बाद सभी लोग हैरान हो गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक काम करना न सिर्फ आपकी पर्सनल और फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि लंबे समय तक काम करने से क्या नुकसान होते हैं और इससे आप कैसे डील कर सकते हैं।

2021 में वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि 2016 में स्ट्रोक और दिल के दौर के कारण लगभग 745000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके पीछे की वजह लंबे समय तक काम करना, नींद ना आना, खराब डाइट और तनाव था। यह सभी कारण आपके दिल पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

लॉन्ग वर्किंग घंटों के नुकसान

लंबे समय तक काम करने से न सिर्फ आपकी फैमिली और पर्सनल लाइफ बाधित होती है, बल्कि यह आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लॉन्ग वर्किंग ऑवर का प्रभाव आपकी डाइट और एक्सरसाइज रूटीन पर भी पड़ता है, क्योंकि आप इन सारी चीजों को कम कर देते हैं और काम पर फोकस करने लगते हैं। इतना ही नहीं ज्यादा समय तक काम करने वाले लोगों को सिगरेट, शराब, चाय, कॉफी जैसी लत भी जल्दी लग जाती है जिसका पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ऐसे में काम और लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।

इस तरह से काम और लाइफ के बीच करें कोऑर्डिनेशन

समय सीमा निर्धारित करें

वर्किंग लोगों के ऊपर हमेशा काम करने का दबाव होता है, लेकिन काम और आराम के बीच समय का कोआर्डिनेशन करना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करें और बीच-बीच में ब्रेक भी लें।

सेल्फ केयर

लॉन्ग वर्किंग ऑवर के साथ-साथ जरूरी है कि आप अपनी खुद की केयर भी करें। एक्सरसाइज के लिए समय निकालें, हेल्दी डाइट लें और समय से सोए और समय से उठें।

घंटे के हिसाब से काम करें

अपना वर्किंग शेड्यूल 8-8-8 के हिसाब से बनाएं, जिसमें 8 घंटे आपको काम करना है, 8 घंटे सोना है और 8 घंटे आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और खुद के लिए निकलना है। इससे एक बैलेंस लाइफ बनी रहती है और स्ट्रेस लेवल भी कम होता है।

शब्द सामर्थ्य -089

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. बात, घटना, माजरा, मुकदमा (उर्दू) 3. अलावा, अतिरिक्त 6. प्रेम, इच्छा 7. मां का बच्चे के प्रति प्रेम 8. गलती, जुर्म, गुनाह, दोष 10. मग्न, लीन, खुश, प्रसन्न 12. धनुष, समादेश, फौजी टुकड़ी 13. एक कल्पित पत्थर जो लोहे को छूकर सोना बना देता है 16. हिम्मत, साहस, सामर्थ्य 17. बनावटी, अनुकृति, असली का विलोम 18. अबोध, नासमझ 20. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध हरिभक्त देवर्षि 22. गहरा नीला, काला 23. व्याकुल, बेसब्र 24. मन, चित्त, आदरसूचक तथा सहमति सूचक एक शब्द।

ऊपर से नीचे

1. स्वामी, नाथ 2. बेबस, मजबूर, विवश 3. अन्याय, अत्याचार, जुल्म 4. मध्य एशिया का एक देश 5. पुस्तक 9. बहादुर, वीर 11. सैनिक विद्रोह 12. नीच, अधम 12 ए. प्रणाम, झुकना 13. भरण-पोषण करना, परवरिश करना, छोटा झूला, हिंडोला 14. प्रमाण, प्रमाणिक कथन 15. स्वाभाविक ढंक, योग्यता, लियाकत, सभ्यता और शिष्टता, शऊर (उ.) 19. बिजली, तड़ित 21. रात में दिखाई न पड़ने का नेत्र संबंधी रोग।

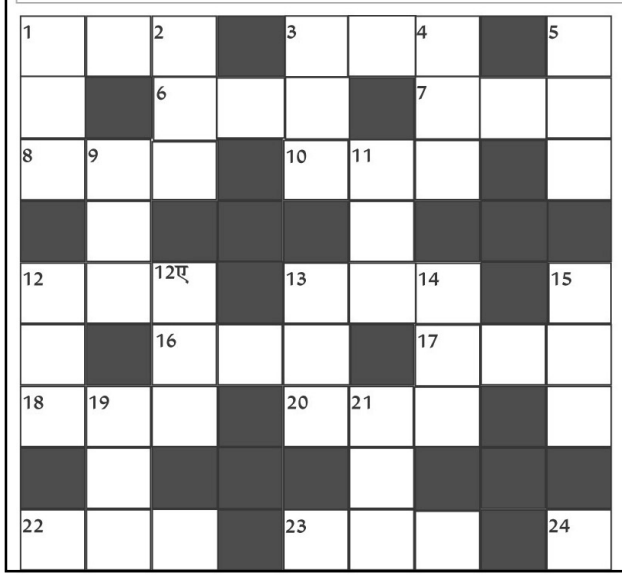

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 88 का हल

प	सं	द	■	सिं	हा	स	न	■
ख	■	म	ज	दू	र	■	का	म
वा	द	क	■	र	■	सं	ब	ल
ड़	■	ल	ज्जा	■	म	स्का	■	य
■	बा	■	■	बि	हा	र	■	■
सु	धा	क	र	■	न	■	■	औ
रं	■	म	■	कि	ता	ब	■	स
ग	■	अ	र	सा	■	हु	ज्ज	त
■	श	क्ल	■	न	मि	त	■	न

रोजाना एक्सरसाइज करने से जुड़े इन भ्रमों को सही मानते हैं लोग!

शारीरिक सक्रियता हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। फिर चाहे यह किसी भी रूप में हो, जैसे रोजाना 30 मिनट टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या तैरना। इससे न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, कई लोग रोजाना एक्सरसाइज करने को लेकर कुछ भ्रम फैलाते हैं। आइए आज हम आपको रोजाना एक्सरसाइज करने से जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई बताते हैं।

भ्रम- ज्यादा पसीना बहाने का मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न होना- यह भी एक सामान्य भ्रम है कि ज्यादा पसीना बहाने का मतलब ज्यादा कैलोरी बर्न होना होता है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि जितना ज्यादा पसीना, उतना ज्यादा जली कैलोरी। दरअसल, पसीना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने का एक तरीका है, न कि यह संकेतक है कि आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। इसलिए, पसीना की मात्रा पर ध्यान देने के बजाय अपनी शारीरिक गतिविधियों और आहार पर ध्यान दें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें।

भ्रम- एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग है जरूरी- शायद आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग करना जरूरी है, लेकिन यह भी एक भ्रम है। दरअसल, एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्मअप करना चाहिए और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बाद करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेचिंग को ज्यादा देर तक करते हैं तो इससे मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। इसलिए, एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्मअप करें और बाद में स्ट्रेचिंग करें।

भ्रम- रोजाना एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में होता है दर्द- रोजाना एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐसा मानना भी एक भ्रम है। अगर आपको एक्सरसाइज करने के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर आपकी तकनीक गलत हो सकती है। एक्सरसाइज के दौरान आपको हल्का तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए। अगर दर्द हो तो थोड़ी देर आराम करें और अपनी तकनीक पर ध्यान दें।

भ्रम- एक्सरसाइज करते समय पेट होना चाहिए खाली- यह भी एक भ्रम है कि एक्सरसाइज करते समय पेट खाली होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो इससे कमजोरी आ सकती है और शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप हल्का नाश्ता करके एक्सरसाइज करें, ताकि आपको ऊर्जा मिल सके और आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन आपको ज्यादा ताकत प्रदान करेगा।

एक खास किस्म का फल है तारा सेब, इसे इन तरीकों से करें डाइट में शामिल

तारा सेब एक खास फल है, जो आकार में तारे की तरह दिखता है और स्वाद में खट्टा-मीठा होता है। यह फल विटामिन-सी, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है। आमतौर पर तारा सेब का सेवन सलाद या ठंडे पेय के रूप में किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसे अन्य कई तरीकों से भी खाया जा सकता है? आइए आज हम आपको तारा सेब के कुछ अनोखे व्यंजनों के बारे में बताते हैं।

तारा सेब का रस बनाकर पिएं- तारा सेब का रस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें विटामिन-सी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तारा सेब को धोकर उसके टुकड़े कर लें, फिर उसे रस निकालने वाले यंत्र में डालकर उसका रस निकालें। इस रस को ताजे पुदीने की पत्तियों और थोड़ी-सी चीनी के साथ मिलाकर पीएं। यह पेय गर्मियों में आपको तरोताजा रखेगा।

तारा सेब की चटनी बनाएं- तारा सेब की चटनी खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तारा सेब को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक मिलाकर पीस लें। इस मिश्रण को थोड़ी देर पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। इस चटनी को पराठे या रोटी के साथ खाया जा सकता है। यह आपके खाने को नया स्वाद देगी और पौष्टिक भी होगी।

तारा सेब का ठंडा मीठा बनाएं- गर्मियों में ठंडा-ठंडा मीठा खाना किसे पसंद नहीं होता? स्टार सेब का ठंडा मीठा बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले स्टार सेब के टुकड़ों को पीस लें, फिर इसमें दूध, चीनी और मलाई मिलाकर जमने के लिए रख दें। कुछ घंटों बाद आपका ठंडा मीठा तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

तारा सेब का मीठा मुरब्बा बनाएं- तारा सेब का मीठा मुरब्बा नाश्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तारा सेब के टुकड़ों को चीनी और नींबू रस के साथ पकाएं, जब तक कि वह गाढ़ा न हो जाएं। इस मुरब्बे को ब्रेड या पराठे पर लगाकर खाया जा सकता है। यह मुरब्बा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन-सी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। इसे ठंडा करके फ्रिज में भी रखा जा सकता है।

तारा सेब का मिल्क शेक बनाएं- सुबह-सुबह ऊर्जा से भरपूर रहने के लिए तारा सेब का मिल्क शेक पीना अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले एक यंत्र में एक तारा सेब का टुकड़ा, आधा केला, थोड़ी दही और शहद डालकर अच्छे से पीस लें। इस मिश्रण को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी-सी पुदीने की पत्तियां डालें।

अरशद वारसी ला रहे डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर!

अभिनेता अरशद वारसी एक डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन भीमा योजना लेकर आ रहे हैं। फिल्म का पहला पोस्टर आज सामने आया है। इस फिल्म में अरशद वारसी डबल रोल में नजर आएंगे। अपने करियर में पहली बार अरशद किसी फिल्म में दोहरी भूमिका निभाएंगे। फिल्म का टीजर रिलीज कियाा गया है। 1 मिनट 16 सेकंड के इस टीजर में कॉमेडी और ड्रामा की पूरी झलक दिखती है। साथ ही दिखता है कि कैसे कॉमेडी ऑफ इरर्स से होता है पूरा हंगामा। टीजर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अरशद वारसी के एक किरदार की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर अरशद का दूसरा किरदार अपने हमशक्ल की मौत का फायदा उठाकर बीमा की रकम हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। इस दौरान टीजर में कई तरह की मुश्किलें आती हैं, जो फिल्म में और भी विस्तार से देखने को मिलेंगी।

अरशद वारसी इस फिल्म में दो हमशक्ल व्यक्तियों की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी जिंदगी अप्रत्याशित और खतरनाक तरीके से एक-दूसरे से जुड़ जाती है। इसके बाद शुरू होती है अपराध, धोखे और डार्क ह्यूमर से भरपूर घटनाएं। %जीवन भीमा योजना' लालच, मजबूरी, प्यार और एक गलत फैसले के दूरगामी परिणामों की कहानी है।

फिल्म जीवन और उसकी पत्नी योजना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनकी जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आता है, जब उन्हें भीमा नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो हूबहू जीवन जैसा दिखता है। दोनों एक ऐसी योजना बनाते ,हैं जिसमें जीवन की मौत का नाटक कर बीमा की रकम हासिल की जा सके। लेकिन यह आसान योजना तब बुरी तरह उलझ जाती है, जब मरा समझा गया व्यक्ति हीरे की तस्करी से जुड़े एक खतरनाक गिरोह से संबंध रखता हुआ निकलता है।

अभिषेक डोगरा द्वारा निर्देशित %जीवन भीमा योजना' अंशु मिश्रा द्वारा स्टार बीम वेंचर्स लिमिटेड के बैनर तले निर्मित है। इस फिल्म में अरशद वारसी के अलावा संजीदा शेख, विजय राज, पूजा चोपड़ा और बिजेंद्र काला जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म की रिलीज तारीख आना बाकी है।

साड़ी पहने स्टाइलिश पोज देती दिखीं मौनी रॉय

अभिनेत्री मौनी रॉय इन दिनों वेब सीरीज अब होगा हिसाब को लेकर सुर्खियों में हैं। यह सीरीज 8 जून को एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई थी। मौनी के अलावा इसमें शाहीर शेख और संजय कपूर भी हैं। इस बीच मौनी अपने साड़ी लुक को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं।

मौनी रॉय ने अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। वे साड़ी पहने स्टाइलिश पोज देती दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, हमेशा एक साड़ी वाली लड़की।

मौनी रॉय गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने लाल रंग के ब्लाउज के साथ कैरी किया है। इसके साथ उन्होंने छोटी सी लाल बिंदी और मैचिंग झुमकों से लुक कंपलीट किया है।

मौनी रॉय का हेयरस्टाइल भी उनके लुक में चार चांद लगा रहा है। उन्होंने बालों को खुला रखा है। लहराती हुई जुल्फों के साथ पोज देते हुए मौनी बला की खूबसूरत लग रही हैं।

मौनी रॉय की तस्वीरों पर नेटिजंस के ढेर सारे रिएक्शन आ रहे हैं। यूजर्स उन्हें भारतीय कल्चर का चांद कह रहे हैं तो कोई लिख रहा है, आपके ऊपर सभी लिबास अच्छे लगते हैं, मगर साड़ी की बात ही अलग है।

मौनी की निजी जिंदगी की बात करें तो पति सूरज नांबियार के साथ उनका सेपरेशन हो गया है। बता दें कि दोनों ने साल 2022 में गोवा में शादी की थी।

उत्तराखंड कांग्रेस का 'सिक्सर'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। कार्यक्रम से पहले कांग्रेस का दावा है कि राज्यभर से बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने इसमें शामिल होने के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। पार्टी इसे युवाओं के बढ़ते समर्थन और बेरोजगारी, शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता का संकेत बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कार्यक्रम के लिए मिले पंजीकरण ने उनकी अपेक्षाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। पार्टी के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में छात्र और युवा जुड़ना चाहते हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन के कुल आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

◆राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए युवाओं में भारी क्रेज का दावा, बोले-रिकार्ड तोड़ हुए रजिस्ट्रेशन

◆कांग्रेस का दावा-प्रदेश हर जिले से उमड़ा पंजीकरण का सैलाब, अब नतीजों पर नजर

◆क्या राहुल गांधी की गूंज बदल पाएगी उत्तराखंड राज्य की चुनावी फिजा, यक्ष प्रश्न !

कांग्रेस का मानना है कि उत्तराखंड का युवा आज रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, शिक्षा और पलायन जैसे सवालों को लेकर गंभीर है। पार्टी इन्हीं मुद्दों पर सीधा संवाद स्थापित कर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

भाजपा ने कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल भीड़ जुटाने या पंजीकरण कराने से युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होता। पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस युवाओं की भावनाओं को चुनावी राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार नीतिगत स्तर पर काम कर रही है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी व्यापक अभियान चलाया है। युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता विभिन्न जिलों में संपर्क अभियान चला रहे हैं और छात्रों को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजीकरण कराने वाले युवाओं में से वास्तविक भागीदारी कितनी होती है और राहुल गांधी अपने संवाद में युवाओं के लिए कौन-सा स्पष्ट राजनीतिक और नीतिगत संदेश देते हैं। यही तय करेगा कि यह पहल केवल एक सफल आयोजन बनकर रह जाती है या उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में एक प्रभावशाली मोड़ साबित होती है।

सू- दोकू क्र.089

	2			6			1	
3			4			2		
							6	
6					4			
	9		5			6		1
4		3			9			2
	8		2				7	
1		2		4		9		6

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.88 का हल

8	7	6	9	5	1	2	3	4
1	3	9	2	8	4	5	6	7
4	5	2	3	7	6	9	1	8
2	8	5	4	6	7	1	9	3
3	1	7	8	9	2	4	5	6
6	9	4	1	3	5	7	8	2
9	4	1	6	2	8	3	7	5
7	2	8	5	1	3	6	4	9
5	6	3	7	4	9	8	2	1

देवभूमि में 'चढ़ावे' पर छिड़ा 'महायुद्ध'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। बदरीनाथ धाम के चढ़ावे में कथित चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। यह उत्तराखंड की राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष भाजपा और विपक्षी कांग्रेस इस मुद्दे को अपने-अपने राजनीतिक नजरिए से जनता के सामने रख रहे हैं। एक ओर भाजपा इसे सरकार की पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे देवभूमि की आस्था के साथ विश्वासघात और सरकारी तंत्र की विफलता के रूप में पेश कर रही है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस प्रकरण में चुनावी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी हैं।

भाजपा नेताओं का कहना है कि धामी सरकार ने मामले को दबाने के बजाय तत्काल संज्ञान लिया। जांच समिति का गठन किया गया, संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए गए। पार्टी का तर्क है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ही सुशासन का प्रमाण है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा इस मामले को जवाबदेह शासन की मिसाल के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष बिना जांच पूरी हुए राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहा है।

दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सरकार को कठघरे में खड़ा कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि यदि मंदिरों के चढ़ावे तक सुरक्षित नहीं हैं, तो सरकार की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठते हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल चोरी नहीं, बल्कि श्र(ालुओं के विश्वास पर चोट है। कांग्रेस इस मुद्दे को व्यापक प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़ते हुए पूछ रही है कि मंदिरों की व्यवस्थाओं की निगरानी कौन कर रहा था, सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई और जिम्मेदारी किसकी तय होगी।

◆बदरीनाथ चढ़ावा चोरी कांड पर भाजपा-कांग्रेस में छिड़ा महासंग्राम
◆बदरीनाथ दान विवाद को चुनावी हथियार बनाने में जुट गए हैं दल
◆त्वरित कार्रवाई का दावा बनाम सरकारी तंत्र की नाकामी की जंग

उत्तराखंड की राजनीति में धार्मिक आस्था हमेशा एक महत्वपूर्ण तत्व रही है। चारधाम यात्रा राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी है। ऐसे में बदरीनाथ धाम से जुड़ा कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक महत्व हासिल कर लेता है। वही भाजपा इस मुद्दे को दोषियों पर कार्रवाई बनाम विपक्ष की राजनीति के रूप में पेश करेगी, जबकि कांग्रेस आस्था की सुरक्षा में सरकार की विफलता को जनता के बीच ले जाने का प्रयास करेगी।

पिछले कुछ समय से कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को उठाती रही है। अब बदरीनाथ चढ़ावा प्रकरण उसके लिए एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा बन सकता है, जो सीधे श्र(ालुओं की भावनाओं से जुड़ता है। यही कारण है कि कांग्रेस इस मामले को विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाने की रणनीति बना सकती है। भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह जनता को विश्वास दिलाए कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों पर अंतिम कार्रवाई भी होगी। यदि जांच लंबी खिंचती है या जिम्मेदारी तय करने में देरी होती है, तो विपक्ष को सरकार पर हमले का और अवसर मिल सकता है।

राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन आम जनता के मन में कुछ बुनियादी सवाल अब भी कायम हैं कि चढ़ावे की सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई? जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? जांच रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या स्थायी व्यवस्था बनेगी? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि यह मामला केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहेगा या फिर उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा।

जनता मिलन कार्यक्रम में 82 शिकायतें दर्ज की

चम्पावत(आरएनएस)। चम्पावत जनता मिलन कार्यक्रम में 82 शिकायतें दर्ज की गई। इस दौरान दस लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। सीडीओ डॉ.जीएस खाती ने अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। चम्पावत कलक्ट्रेट में सोमवा को जनता मिलन कार्यक्रम हुआ। लोहाघाट निवासी किशन सिंह ने आधार कार्ड में जन्मतिथि सुधार कराने में आ रही समस्या, सिमियाउरी के अमन सिंह ने बिजली के खंभे व लटकते तार ठीक करने, चम्पावत के नागनाथ वार्ड निवासी कमल जोशी एवं अन्य लोगों द्वारा नाला निर्माण करने की मांग की।

बढ़े बिजली बिलों पर सरकार और ऊर्जा निगम को घेरा

बागेश्वर(आरएनएस)। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने बिजली बिलों में लगातार हो रही भारी बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश सरकार और ऊर्जा निगम पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख और डेढ़ लाख रुपये तक के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, जबकि कई उपभोक्ता नियमित रूप से बिल जमा करते रहे हैं। ऐठानी ने कहा कि ऊर्जा निगम पुराने मीटरों में खराबी का हवाला देकर उपभोक्ताओं पर मनमाने बिल थोप रहा है। साथ ही अब स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है।उनका आरोप है कि बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी खुलकर आवाज नहीं उठा रहे हैं, जिससे आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार इतने भारी-भरकम बिजली बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के बजाय अनदेखी कर रही है। ऐठानी ने बताया कि फरवरी में कपकोट में आयोजित महापंचायत के दौरान ऊर्जा निगम को 43 शिकायतें मिली थीं। इस संबंध में मामला जिलाधिकारी के समक्ष भी उठाया गया, लेकिन अब तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।

अल्मोड़ा के युवा वैज्ञानिक डॉ. कुलदीप रौतेला को कनाडा की प्रतिष्ठित पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप

अल्मोड़ा(आरएनएस)। अल्मोड़ा जिले के युवा वैज्ञानिक डॉ. कुलदीप सिंह रौतेला का चयन कनाडा की प्रतिष्ठित कनाडा इम्पैक्ट रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स (सीआईआरटीए) पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप के लिए हुआ है। दो वर्ष की इस शोधवृत्ति के तहत वह कनाडा के विश्वप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ता के रूप में वनाग्नि, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर शोध करेंगे। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए भारत से चुनिंदा शोधकर्ताओं का ही चयन किया गया है। डॉ. रौतेला का शोध वनाग्नि, वायुमंडलीय एरोसोल धाराओं, पीएम 2.5 प्रदूषण और इनके मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर केंद्रित रहेगा। उनका अध्ययन यह समझने में मदद करेगा कि जंगलों की आग से निकलने वाला धुआं किस प्रकार हजारों किलोमीटर तक फैलकर वायु प्रदूषण बढ़ाता है और मानव स्वास्थ्य, हिमालयी पारिस्थितिकी तथा जलवायु को प्रभावित करता है। इस शोध से भविष्य में वनाग्नि की निगरानी, वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। मूल रूप से हवालबाग विकासखंड के कयाला गांव निवासी डॉ. कुलदीप सिंह रौतेला ने बीटीकेआईटी द्वाराहाट से बीटेक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एमटेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर से पीएचडी की है। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तथा आईआईटी इंदौर में विभिन्न शोध परियोजनाओं पर कार्य किया है। उनका शोध जलवायु परिवर्तन, हिमालयी जल संसाधन, वायु प्रदूषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग और चरम जलवायु घटनाओं जैसे विषयों पर केंद्रित रहा है। डॉ. रौतेला अब तक 44 अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं। इसके अलावा वह एक पुस्तक तथा दो पेटेंट के लेखक एवं सह-लेखक भी हैं। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के क्षेत्र में उनके शोध कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के विभिन्न समसामयिक विषयों तथा राज्यहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच उत्तराखण्ड के समग्र विकास, जनकल्याण, सुशासन एवं जनसरोकारों से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

गणेश गोदियाल व यशपाल आर्य ने की राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल की समीक्षा

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य व प्रीतम सिंहा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पहुंचक समीक्षा की।

आज यहां उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विपक्ष के नेता यशपाल आर्य, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता प्रीतम सिंह और अन्य नेता बन्नू स्कूल के मैदान में गए और 17 जुलाई को प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप, सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव, देहरादून कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सलाहकार सरदार अमरजीत सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे।

भाजपा के भीतर 'बगावत के सुर'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

देते हैं कि सत्ता की चमक के पीछे संगठन के भीतर असंतोष की परतें भी मौजूद हैं। यदि इन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो यही परतें चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकती हैं।

भाजपा के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि संगठन केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं चलता, बल्कि उन हजारों कार्यकर्ताओं के विश्वास से चलता है जो बिना किसी पद और प्रचार के वर्षों तक पार्टी का झंडा उठाए रहते हैं। यदि वही कार्यकर्ता एक दिन यह सवाल पूछने लगें कि क्या हम सिर्फ झंडे-डंडे उठाने के लिए हैं? तो समझ लेना चाहिए कि नाराजगी अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक चौपाल तक पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि भाजपा नेतृत्व इस घटनाक्रम को साधारण अनुशासनहीनता मानकर नजरअंदाज करता है या इसे संगठन के भीतर बजी खतरे की घंटी समझकर आत्ममंथन करता है। क्योंकि चुनावी राजनीति में विरोधियों के हमले जितना नुकसान नहीं पहुंचाते, उससे कहीं अधिक नुकसान अपने घर की नाराजगी पहुंचा सकती है।

3000 पेड़ों के लिए 'जेन जी' सड़क..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

जाएगा? क्या स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की राय ली गई? क्या प्रतिपूरक पौधरोपण की निगरानी होगी? इन सवालों के जवाब केवल आंदोलनकारियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एक समय कहा जाता था कि नई पीढ़ी को पर्यावरण से ज्यादा इंटरनेट की चिंता है। लेकिन देहरादून की सड़कों पर उतरी भीड़ ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। यह जेन-जी अब केवल रील नहीं बना रही, बल्कि पेड़ों के लिए आवाज भी उठा रही है। 3000 पेड़ों की कटाई का विरोध केवल एक परियोजना के खिलाफ आंदोलन नहीं है। यह उस सोच के खिलाफ आवाज है, जिसमें विकास को केवल कंक्रीट और डामर से मापा जाता है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जो सड़क भी बनाए और जंगल भी बचाए। क्योंकि उत्तराखंड की पहचान उसकी चौड़ी सड़कों से नहीं, बल्कि उसके देवदार, बांज, बुरांश, नदियों और जंगलों से है। यदि यही पहचान खत्म हो गई तो विकास के आंकड़े भले बढ़ जाएं, लेकिन पहाड़ अपनी आत्मा खो देगा।

पराग फार्म में बनेगी राज्य की अपनी एविएशन एकेडमी: मुख्य सचिव

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश को हेलिपोर्ट्स एवं हेलीपैड से सैचुरेट करने की आवश्यकता है। ये हमारे जैसे प्रदेश के लिए लाइफलाइन साबित होंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून को प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों को हवाई सेवा से जोड़ा जाए। मुख्य सचिव ने पौड़ी जनपद को भी नियमित हवाई सेवा से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन उत्तराखण्ड के मुख्य हिल स्टेशनों में से एक है। लैंसडाउन को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की सम्भावनाएं तलाशी जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अपना पायलट ट्रेनिंग स्कूल तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि उधमसिंह नगर के पराग फार्म में एविएशन एकेडमी स्थापित की जाए। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को आवश्यकत प्रक्रियाएं शुरू किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम के लिए एयर ट्रेफिक कंट्रोल शीघ्र स्थापित किए जाने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि ज्ञातव्य हो कि एयर ट्रेफिक कंट्रोल स्थापित करने में सिविल वर्क राज्य सरकार एवं मैन पॉवर और तकनीकी सहायता एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार हवाई सेवाओं का विस्तार हो रहा है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रदेशभर में एयर ट्रेफिक कंट्रोल मैकेनिज्म स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि हवाई यात्राएं सुरक्षित हो सकें। उन्होंने युकाडा को प्रदेशभर में एटीसी सैचुरेशन का लक्ष्य देते हुए इस सम्बन्ध में एयरपोर्ट अथॉरिटी से लगातार सम्पर्क किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस) एवं पीटीजेड कैमरा स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत मौसम विभाग से अनुरोध कर इस दिशा में लगातार फॉलाअप किया जाए। मुख्य सचिव ने दूर-दराज और कम सेवा वाले इलाकों में मजबूत हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने के भी निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने प्रदेशभर में हेलीपोर्ट्स एवं हेलीपैड्स से सैचुरेट किए जाने पर जोर दिया।

भानियावाला-जॉलीग्रांट हाईवे चौड़ीकरण में वृक्ष कटान रोकने की मांग

संवाददाता

देहरादून। भानियावाला-जॉलीग्रांट-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के दौरान प्रस्तावित वृक्ष कटान को लेकर संयुक्त नागरिक संगठन ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, एनएचएआई और प्रमुख वन संरक्षक को पत्र भेजकर पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने की मांग की है।

संगठन ने कहा कि वह सड़क चौड़ीकरण, चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक बेहतर संपर्क का समर्थन करता है, लेकिन विकास के नाम पर बड़ी संख्या में पुराने वृक्षों की कटाई उचित नहीं है। संगठन के अनुसार प्रस्तावित लगभग 20 किलोमीटर का मार्ग राजाजी क्षेत्र के वन क्षेत्र से होकर गुजरता है, जहां पीपल, बरगद और साल जैसे दशकों पुराने वृक्ष मौजूद हैं, जो पर्यावरण संतुलन और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संगठन के सचिव सुशील त्यागी ने कहा कि जहां 50 से 100 वर्ष पुराने वृक्ष हैं, वहां सड़क की डिजाइन में आवश्यक बदलाव कर या सीमित दूरी तक एलिवेटेड रोड बनाकर पेड़ों को बचाया जा सकता है। उन्होंने छोटे वृक्षों को काटने के बजाय सुरक्षित रूप से दूसरी सरकारी भूमि पर प्रतिरोपित करने तथा प्रत्येक कटने वाले वृक्ष के बदले कम से कम 10 पौधे लगाने और उनकी तीन वर्षों तक देखभाल सुनिश्चित करने की भी मांग की।

पत्र में देहरादून शहर की लगातार बढ़ रही यातायात समस्या का भी उल्लेख किया गया है। संगठन ने शहर के प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड परियोजना को ट्रैफिक जाम के स्थायी समाधान के रूप में अपनाने का सुझाव देते हुए सरकार से इस दिशा में ठोस पहल करने की अपील की है।

रेहड़ी पटरी वर्कर्स यूनियन ने शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रैली निकाली

संवाददाता

देहरादून। सीटू से संबद्ध रेहडी पटरी वर्कस यूनियन ने डीएल रोड, सीमेंट रोड व करनपुर बाजार में नगर निगम के द्वारा रेहडी पटरी व्यवसायियों के उत्पीडन के खिलाफ रैली निकाल कर प्रदर्शन किया।

आज सीटू से संबद्ध रेहड़ी पटरी-वर्कर्स यूनियन देहरादून ने डी. एल रोड , सीमेंट रोड व करनपुर बाजार क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के उत्पीड़न के खिलाफ रैली निकाल कर व एक घंटे की हड़ताल कर विरोध किया ।इस अवसर पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जम कर नारेबाजी की गई। रैली 5 सीमेंट रोड स्थित छात्रावास से शुरू हुई।

इस अवसर पर सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने कहा कि पिछले कई दशकों से रेहड़ी पटरी लगा कर स्थानीय लोग जो रिस्पना के किनारे बस्तियों में रहते हैं के द्वारा यह व्यवसाय किया जाता है जिससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। किंतु पिछले दिनों से नगर निगम प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिससे इनकी रोजीरोटी पर हमला हो रहा है इसके खिलाफ सीटू द्वारा इनकी यूनियन का गठन किया गया है ओर सीटू ही इनकी लड़ाई लड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इन्हें उक्त स्थानों पर ही वेंडर जोन घोषित कर जगह आवंटित की जाए और नगर निगम देहरादून इनका शोषण पर रोक लगाए। इस अवसर पर उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगरनिगम द्वारा इनका उत्पीड़न नहीं रोका जाता है तो वे समस्त देहरादून के रेहड़ी पटरी वर्कर्स को संगठित कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा और नगर निगम सहित प्रदूषकों भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर सीटू के जिला सचिव अभिषेक भंडारी, यूनियन के महामंत्री मनीष कुमार, अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर आदि ने विचार व्यक्त किये।

बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामलाः खजांची हटाया, कई और कर्मचारी भी रडार पर

हमारे संवाददाता

चमोली/देहरादून। बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे में हेराफेरी का मामला अब केवल एक कर्मचारी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया है। शासन की ओर से गठित उच्चस्तरीय जांच समिति ने मामले की तह तक पहुंचने के लिए 14 जुलाई को बदरीनाथ धाम में डेरा डाल दिया है। आईएएस अधिकारी एवं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के नेतृत्व में समिति दान-चढ़ावे की गणना प्रक्रिया, अभिलेखों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की बारीकी से जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर, एसआईटी की जांच में नए नाम सामने आने के बाद मंदिर समिति के भीतर भी कार्रवाई शुरू हो गई है।

वैयक्तिक सहायक प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद बदरी-केदार मंदिर समिति ने खजांची संदेश मेहता को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा मंदिर समिति के तीन अन्य कर्मचारियों और एक श्रद्धालु की भूमिका भी जांच के घेरे में है।

सूत्रों के मुताबिक, तीनों कर्मचारियों को नोटिस दिए जाने की तैयारी है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले श्रद्धालु से पूछताछ की जाएगी। आईएएस आनंद स्वरूप के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय समिति ने बदरीनाथ पहुंचकर एसआईटी और मंदिर समिति के अधिकारियों से अब तक की जांच का विस्तृत ब्यौरा लिया। समिति ने उस स्थान का भी निरीक्षण किया, जहां दानपात्रों से निकले चढ़ावे की गणना की जाती है। गणना की पूरी प्रक्रिया को समझने के साथ-साथ कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। समिति ने दान-चढ़ावे की गणना से जुड़े सभी अभिलेख, रजिस्टर और दस्तावेज एसडीएम ज्योतिर्मठ के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान चांदी से संबंधित रिकॉर्ड में ओवरराइटिंग मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिसे जांच समिति ने गंभीरता से लिया है। माना जा रहा है कि रिकॉर्ड में की गई किसी भी तरह की काट-छांट या बदलाव की फोरेंसिक और प्रशासनिक स्तर पर भी पड़ताल कराई जा सकती है। फिलहाल, जांच का केंद्र 25 जून से 2 जुलाई के बीच हुई दान-चढ़ावे की गणना है। इस अवधि के सीसीटीवी फुटेज और अभिलेखों को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, 25 जून को गणना के दौरान एक श्रद्धालु के अपनी जेब में कुछ सामग्री रखने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। उसकी पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि वह विष्णुप्रयाग परियोजना से जुड़ा हुआ है और पूर्व में भी गणना प्रक्रिया में शामिल होता रहा है। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि बदरीनाथ मंदिर परिसर में कुल 26 दानपात्र स्थापित हैं। इनमें मंदिर के भीतर दो, परिसर में तीन तथा सिंहद्वार सहित अन्य स्थानों पर 21 दानपात्र लगे हुए हैं। इन सभी दानपात्रों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक साथ खोला जाता है और मंदिर अधिकारी तथा सहायक मंदिर अधिकारी की मौजूदगी में दान-चढ़ावे की गणना की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले लगे नये सीसीटीवी कैमरों में चोरी की यह घटना रिकार्ड हुई है। पुराने कैमरों में स्टोरेज की सीमा दो हफ्ते तक ही थी। नये कैमरे करीब 32 जगह लगाए गए हैं।

शासन की उच्चस्तरीय समिति और एसआईटी की समानांतर जांच से स्पष्ट है कि सरकार इस मामले को केवल विभागीय अनियमितता के रूप में नहीं, बल्कि आस्था और पारदर्शिता से जुड़े गंभीर प्रकरण के रूप में देख रही है।जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हेराफेरी की घटनाएं व्यक्तिगत स्तर तक सीमित थीं या इसके पीछे कोई संगठित तंत्र काम कर रहा था। आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी एवं कर्मचारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। कमिश्नर आनन्द स्वरूप, एमडी जीएमवीएन संदीप तिवारी व वित्त सेवा के जगत सिंह चौहान की उच्च स्तरीय जांच टीम विशेष दर्शनों में पर्ची काटे जाने समेत कई अन्य बिंदुओं पर फोकस करेगी तो कुछ और गड़बड़ी सामने आएगी। पर्ची काटने का मुद्दा भी काफी गरमाया हुआ है।

इधर, देहरादून में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत दिवेद्वी व गणेश गोदियाल के बीच चढ़ावा चोरी और प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति को लेकर वाकयुद्ध जारी है। विपक्षी दलों ने बीकेटीसी अध्यक्ष से इस्तीफे की भी मांग की है।

पिरान कलियर में भी होता है चढ़ावा चोरीः विधायक मोहम्मद शहजाद

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। देव भूमि उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ के बाद अब धर्मनगरी में भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान यह बाद विधायक मो. शहजाद द्वारा कबूल की गयी है।

विधायक मो. शहजाद का कहना है कि देवभूमि में सिर्फ बद्रीनाथ मंदिर में ही चोरी नही हो रही है। यहां अगर जांच करायी जाये तो यहां आस्था के सभी क्षेत्रों में प्रशासन की मिली भगत से चोरी की जा रही है। उन्होने कहा कि विश्व प्रसिद्व पिरान कलियर में भी लगातार चोरी चल रहीं है।

उन्होने कहा कि श्रद्वालुओं की आस्था में ठेस लगाने वाले लोगों में प्रशासन के लोग भी शामिल है। अगर सही ढंग से जांच की जाये तो आस्था के अस्थलों पर चढ़ावा मामले रूक जायेगें। सरकार को चाहिए कि इन मामलों को वह गम्भीरता से लें।

अगर कोई रिश्वत मांगे तो मुझे बताएंः विजय

संवाददाता

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और कहा कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी हरकतें जारी रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी।करूर में एक रैली को संबोधित करते हुए, विजय ने लोगों से अपील की कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो वे देने से इनकार कर दें। लोगों को भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनके साथ हैं और उनसे कहा कि जब कोई रिश्वत मांगे तो वे मजबूती से नहीं कहें।

उन्होंने रैली में कहा, जब कोई आपसे रिश्वत मांगे, तो उन्हें सीधे कह दें कि आप नहीं देंगे। मैं आपके साथ रहूंगा। उसके बाद भी अगर कोई आप पर दबाव डाले, तो उनसे कहें, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा विजय इस राज्य पर राज कर रहा है। उन्हें बहुत मजबूती से कहें। उनकी इस बात पर लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं और उनका उत्साह बढ़ाया।

उन्होंने आगे कहा, जब आप मेरे साथ हैं, तो भ्रष्टाचार, रिश्वत लेने या सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें जारी नहीं रख पाएगा।

डीएमके के सीनियर नेता टी.के.एस. इलांगोवन ने विजय सरकार पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। पिछली डीएमके सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए, मंत्री ने टीवीके के अंदरूनी मतभेदों की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी के एक वकील ने मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक सीनियर नेता और जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के वकीलों की नियुक्ति के लिए 1 लाख से 20 लाख तक की रिश्वत ली। इलांगोवन ने कहा, ये आरोप हमने नहीं लगाए हैं; उनकी ही पार्टी के एक वकील कोर्ट गए थे। अगर आप इस बारे में विजय से पूछें, तो शायद उनके पास इसका जवाब हो।

मोबाइल लूट मामले में दो लोग गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल बरामद कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली प्रेम नगर पर कुमारी संतोषी जोशी निवासी ठाकुरपुर प्रेम नगर ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया की केहरी गांव फ्लाईओवर के नीचे से अपने घर की ओर जाते समय पीछे से आये अज्ञात स्कूटी सवार व्यक्ति उसके हाथ से मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत उसके खुलासे तथा गिरफ्तारी हेतु एसएसपी के निर्देशों पर कोतवाली प्रेम नगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित टीम द्वारा घटना स्थल व उसके आस पास आने जाने वाले मार्गो पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजो का अवलोकन करते हुए घटना में शामिल आरोपी के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान झाझरा पुलिस चौकी के सामने से घटना में शामिल 02 लोगों फरमान पुत्र इकरार निवासी लालपुल, पटेल नगर मूल पता बिजनौर, उत्तर प्रदेश तथा सुहेल पुत्र मुरसलीन निवासी ब्रह्मपुरी, पटेल नगर को घटना में छीने गये मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वे दोनों नशे के आदी है तथा अपनी नशे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके द्वारा मोबाइल स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।